

प्रेषक,

जयदेव सिंह,  
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. श्री हिमांशु मेहरा  
अधिवक्ता,  
मा0 उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली-110001

2. श्री मनोज गोरखेला,  
अधिवक्ता,  
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया,  
नई दिल्ली-110001

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु  
पैनल एडवोकेट के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको पैनल अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया है।

2- उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

3- आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-123/XXXVI(1)/2013-43-एक(1)/03 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

4- साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सहमत हो तो कृपया अपनी लिखित सहमति, आयु एवं एडवोकेट के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा आवासीय पता दूरभाष संख्या के साथ उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(जयदेव सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या:55/XXXVI(1)/2012-75/2007 टी0सी0 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महाधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 3- महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 4- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के निजी सचिव।
- 5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 6- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 10- ईरला चैक अनुभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(मन्मथ मिश्र)  
अपर सचिव